



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2006/भाद्र 8, 1928

No. 126]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2006/BHADRA 8, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 28 अगस्त, 2006

सं. टीएमपी/68/2005-आईजीटीपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, आदेश सं. टीएमपी/68/2005-आईजीटीपीएल दिनांक 11 मई, 2006 को संलग्न आदेशानुसार संशोधित करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएमपी/68/2005-आईजीटीपीएल

इंडिया गेटवे टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक

आदेश

(अगस्त 2006 के 23 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने ररिसयों से बांधने / खोलने, मंडारण आयोजना प्रभार और पर्यवेक्षण प्रभार लगाने हेतु इंडिया गेटवे टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 11 मई 2006 को आदेश सं. टीएमपी/68/2005-आईजीटीपीएल पारित किया गया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 30 मई 2006 को राजपत्र सं. 91 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। कथित आदेश में इस प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2005 के, पिछले प्रभाव से निम्नलिखित समेकित प्रभारों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है :-

अनुसूचि 3.7 - जलयान पर स्टीवेजोरिंग प्रभार

विवरण	दर प्रति कन्टेनर	
	विदेशी (अमरी. डालर में)	तटीय (रुपयों में)
बांधने खोलने / मंडारण आयोजना और पर्यवेक्षण प्रभार	7.86	210/-

2.1. कथित आदेश के संदर्भ से कोच्चि स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (सीएसए) ने विभिन्न मुद्दों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात्, 18 जुलाई 2006 को जब कोच्चि पत्तन न्यास आईजीटीपीएल के कुछ अधिकारी और कन्टेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन (इंडिया) के कुछ सदस्य उपस्थित थे, इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर अपना मत रखने का सीएसए को एक अवसर प्रदान किया गया था। सीएसए द्वारा अपने लिखित पक्ष और सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

- आईजीटीपीएल ने 1 अप्रैल 2005 से प्रासंगिक सेवाएं प्रदान नहीं की और, इसलिए, उन्हें इस आधार पर पिछले प्रभाव से बिल नहीं प्रस्तुत करना चाहिए कि प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2005 से दरें अनुमोदित कर दी थीं।
- यदि ये प्रभार पिछले प्रभाव 1 अप्रैल 2005 से लगाए जाते हैं तो शिपिंग लाइनें, जारी औद्योगिक विवाद को ध्यान में रखते हुए, दो बार अर्थात् एक बार आईजीटीपीएल को और दूसरी बार मिजी टर्मिनल प्रचालक को, मंडारण आयोजना और पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान करना बंद कर देंगी।

- (iii) आईजीटीपीएल ने मात्र जुलाई 2005 से पोत पर बांधने / खोलने का काम हाथ में लिया है और एसोसिएटिड यार्ड सर्विसिस ने जनवरी 2006 से, इसलिए, पिछले प्रभाव 1 अप्रैल 2005 से, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों पर ये प्रभार शिपिंग लाइनों द्वारा पूरा-पूरा भुगतान करना न तो स्वीकार्य होगा और न ही न्यायोचित होगा।
- (iv) इस गतिविधि के लिए समेकित प्रभारों को तोड़ा जाए, खंडित किया जाए।
- (v) इसने अनुरोध किया है कि पोत पर स्टीवेडरिंग में भंडारण आयोजना तथा पर्यवेक्षण की मद में शामिल रु. 125/- के प्रभारों को औद्योगिक विवाद सुलझने तक प्रास्थगित रखा जाए।
- (vi) कुछ ठेकेदारों द्वारा उद्धृत दर के दस्तावेजी साक्ष्यों में, जो रु. 250/- प्रति कन्टेनर की दर के लिए आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, बांधने / खोलने के कार्य के अलावा भी कुछ अन्य सेवाएं शामिल हैं। प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के किसी दस्तावेजी साक्ष्य की मांग नहीं की गई थी, और यदि इनकी मांग की जाती तो सीएसएए उन्हें निश्चित रूप से प्रदान करता, क्योंकि रु. 150/- प्रति कन्टेनर (बाक्स) की दर टीएचसी विवरण का अन्तरंग भाग थी।
- (vii) आईजीटीपीएल द्वारा उद्धृत दर ने, प्रासंगिक प्रभार निर्धारित करते समय प्राधिकरण द्वारा जिस का आधार बनाया गया था, उसने बाजार की स्थिति को ठीक-ठीक समाहित नहीं किया। इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने हेतु निजी ठेकेदारों द्वारा इससे पहले लगाई गई दरें, आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की दरों से कम थीं।

2.2. टर्मिनल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ कोच्चि (टीओएके) ने भी सीएसएए द्वारा उठाए गए बिन्दुओं में से अधिकतर पर जोर देते हुए अपना लिखित पक्ष रखा है।

3.1 सीएसएए और टीओएके द्वारा प्रस्तुत किए गए उनके लिखित पक्ष आईजीटीपीएल को उसकी टिप्पणियों के लिए भेज दिए गए हैं। प्रत्युत्तर में आईजीटीपीएल ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं और 16 जुलाई 2006 को आयोजित सुनवाई में विभिन्न बिन्दुओं को स्पष्ट किया है।

सीएसएए द्वारा प्रस्तुत पक्ष के प्रत्युत्तर में आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत व्याख्या निम्नानुसार है :-

- (i) प्राधिकरण के आदेश को भावी प्रभाव से कार्यान्वित किया गया है और बिल केवल उस वास्तविक तिथि से ही प्रस्तुत किए गए हैं जिस तिथि से प्रासंगिक सेवाएं उन्हें दी जानी आरंभ की गई थी। गलतफहमी से बचने के लिए प्राधिकरण वह तिथि विनोदित करने हेतु जिस तिथि से सेवाएं आरंभ की गई थीं, आदेश में संशोधन कर सकता है।
- (ii) इसे समेकित प्रभारों को, निम्नानुसार दो भागों में बांटने पर कोई आपत्ति नहीं है :-
 (क) कन्टेनरों को बांधना / खोलना - रु.225/-
 (ख) भंडारण आयोजना - रु.125/-
- (iii) उन्होंने आगे यह घोषणा की कि टर्मिनल यह सेवा 1 अगस्त 2006 से प्रदान नहीं करेगा और इन प्रचालनों के लिए एजेंट अपनी-अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं। तथापि यह एजेंटों उस विगत अवधि के लिए प्रभार लगाएगा जिस अवधि में उसने वास्तव में सेवाएं दी थीं।
- (iv) प्रदत्त सेवाओं की लागत आईजीटीपीएल द्वारा अपनाने की अपेक्षा करके सीएसएए अपने और अपने कर्मचारियों के बीच औद्योगिक विवाद का बोझ स्थानान्तरित न करे।

3.2. सुनवाई में उठाए गए विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, आईजीटीपीएल, सीएसएए और सीओपीटी को निम्नलिखित कार्रवाई आरंभ करने की सलाह दी गई थी :-

- (i) आईजीटीपीएल वह वास्तविक तिथि सूचित करे जिस तिथि से उनके द्वारा प्रासंगिक सेवाएं प्रदान की गई थीं। यह सूचना देते समय उन्हें इस तिथि पर सीएसएए की सहमति भी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- (ii) यह दिखाने के लिए कि आईजीटीपीएल द्वारा उद्धृत दर ठीक नहीं थीं, सीएसएए, प्रासंगिक सेवा प्रदाताओं के बीच हुए अनुबंध की प्रतियां सीओपीटी के सम्मक्ष प्रस्तुत करे। यह दिखाने के लिए कि ये सेवाएं आईजीटीपीएल द्वारा अधिग्रहित करने से पहले ऐसी दर पर्याप्त रूप से दीर्घकाल से बाजार में प्रचलित दर थी।
- (iii) सीओपीटी को सीएसएए द्वारा किए गए दावे की अधिकृतता का सत्यापन करना चाहिए और अपनी सिफारिशों प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी चाहिए।

4.1 सुनवाई में लिए गए निर्णयों के संदर्भ से, आईजीटीपीएल ने, निर्गम की तिथि पर सीएसएए के सहमति पत्र के साथ प्रासंगिक सूचना / स्पष्टीकरण निम्नानुसार प्रस्तुत कर दिया है :-

- (i) आईजीटीपीएल ने बांधने / खोलने की सेवाएं प्रदान करना 1 जुलाई 2005 से आरंभ किया।
- (ii) भंडारण आयोजना और पर्यवेक्षण से संबंधित सेवाएं अक्टूबर 2005 से प्रदान की गई थीं, तथापि इस सेवा के लिए प्रभार 1 जुलाई 2006 से प्रभारित किए गए थे क्योंकि प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रतीक्षा थी।

- (iii) आईजीटीपीएल द्वारा अग्रेषित सीएसएए का पत्र भी इस बात की पुष्टि करता है कि आईजीटीपीएल द्वारा बांधने / खोलने संबंधी सेवाएं आरम्भ करने की तिथि 1 जुलाई 2006 है।

भंडारण आयोजना और पर्यवेक्षण के बारे में सीएसएए ने बताया है कि चूंकि निजी टर्मिनल प्रचालकों से यह सेवा जनवरी 2006 तक प्रदान करने की अपेक्षा थी, आईजीटीपीएल द्वारा यह प्रशुल्क मद केवल 1 जनवरी 2006 से ही लगाई जा सकती है।

4.2. सीओपीटी ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया है:-

- (i) इसमें पुष्टि की है कि आईजीटीपीएल द्वारा बांधने / खोलने की सेवाएं आरम्भ करने की तिथि 1 जुलाई 2005 है और भंडारण-आयोजना और पर्यवेक्षण आरम्भ करने की तिथि 1 अक्टूबर 2005 है।
- (ii) इसने, सीएसएए द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की है:-
- (क) कोच्चि स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (सीएसएए) ने दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में फीडर पोत प्रचालकों से प्राप्त प्रमाणपत्र और बिल अग्रेषित किए हैं जो दर्शाते हैं कि एमएलओ से बांधने / खोलने संबंधी प्रभार के रूप में रु. 150/- प्रति बाक्स / कन्टेनर प्रभारित किया गया था, किन्तु उन्होंने प्रासंगिक सेवा प्रदाताओं और लाइनरों के बीच हुए ऐसे किसी करार की प्रति नहीं अग्रेषित की जो यह दर्शाए कि आईजीटीपीएल द्वारा उद्धृत दर ठीक नहीं हैं।
- (ख) दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत किए गए बिल 2004 से मार्च 2005 तक की अवधि से संबंधित हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रु. 150/- प्रति बाक्स / कन्टेनर बाजार में, आईजीटीपीएल द्वारा ये सेवा 1 जुलाई 2005 से अधिग्रहीत करने से पूर्व पर्याप्त लम्बी कालावधि तक प्रचलित था।
- (ग) आईजीटीपीएल द्वारा टर्मिनल अधिग्रहीत करने से पहले, बांधने / खोलने की मद में रु. 150/- प्रति बाक्स / कन्टेनर प्रभारित किया जाता था। आईजीटीपीएल द्वारा लगाई जा रही रु. 225/- प्रति बाक्स / कन्टेनर की वर्तमान दर निविदा दाता प्रक्रियाओं से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर है। आईजीटीपीएल ने कन्टेनर बांधने / खोलने संबंधी सेवाएं चलाने के लिए ताजा निविदाएं आमंत्रित की थीं और प्राप्त हुआ न्यूनतम प्रस्ताव रु. 230/- प्रति बाक्स / कन्टेनर था। जिन फर्मों ने वर्तमान निविदा में भाग लिया है, उन्होंने विगत समय में रु. 150/- प्रति बाक्स का प्रस्ताव दिया था किन्तु वर्तमान बाजार दर के अनुसार न्यूनतम भाव प्रस्ताव रु. 230/- प्रति बाक्स है। अतएव, बांधने / खोलने के लिए आईजीटीपीएल द्वारा उद्धृत रु. 225/- प्रति बाक्स की दर न्यायोचित है।

5. प्रस्तुत की गई सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है:

- (i) आईजीटीपीएल, सीओपीटी और सीएसएए सभी ने एकमत से इस बात की पुष्टि की है कि आईजीटीपीएल द्वारा बांधने / खोलने सेवाएं आरम्भ करने की तिथि 1 जुलाई 2005 है। इस बारे में किसी भी विसंगति से बचने के लिए आईजीटीपीएल ने तो सुझाव दिया है कि जिस तिथि से प्रशुल्क लगाया जाना है, वह विनिर्दिष्ट कर दी जाए। ऐसी स्थिति में, पिछले आदेश को यह विनिर्दिष्ट करने के लिए संशोधित किया जाता है कि बांधने / खोलने के लिए प्रशुल्क 1 जुलाई 2005 से लागू होगा।
- (ii) भंडारण आयोजना और पर्यवेक्षण के लिए प्रभारों के बारे में सीएसएए ने एक अस्पष्ट सी टिप्पणी की है कि यह प्रशुल्क 1 जनवरी 2006 से इस आधार पर लगाया जा सकता है कि निजी प्रचालकों को उस अवधि तक यह सेवा प्रदान करने की अनुमति थी। उसने आईजीटीपीएल द्वारा यह सेवा आरम्भ करने की तिथि के बारे में, विशिष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। आईजीटीपीएल को यह प्रशुल्क उस तिथि से लगाने का अधिकार है जब से इसने यह सेवा प्रदान करना आरम्भ किया है।

आईजीटीपीएल ने बताया है कि भंडारण आयोजना से संबंधित सेवाएं 1 अक्टूबर 2005 से प्रदान की गई थीं। सीओपीटी ने भी अपनी ओर से सत्यापन करने के बाद इस बात की पुष्टि की है कि आईजीटीपीएल द्वारा भंडारण आयोजना और पर्यवेक्षण सेवाएं 1 अक्टूबर 2005 से ही प्रदान की गई थीं। ऐसी स्थिति में, यह विनिर्दिष्ट करने के लिए कि भंडारण आयोजना / पर्यवेक्षण के लिए प्रशुल्क 1 अक्टूबर 2005 से ही लागू होगा, पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन किया जाता है।

- (iii) इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वर्तमान दर को खंडित करने हेतु सीएसएए ने सुझाव दिया है। सम्भवतः इसकी आवश्यकता है क्योंकि इन दो सेवाओं के प्रशुल्क को अलग-अलग स्थितियों से लागू किया जाना है। वर्तमान दर को दो खंडों में अर्थात् बांधने / खोलने संबंधी प्रभार और भंडारण आयोजना तथा पर्यवेक्षण प्रभार में बांटने पर आईजीटीपीएल ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

आईजीटीपीएल ने, स्वयं अपने आरम्भिक प्रस्ताव में पोत पर सम्मिश्र स्टीवेजोरिंग दर के अवयव दर्शाए थे और इनका उल्लेख 11 मई 2006 के आदेश में भी हुआ है। सम्मिश्र दर को दो खंडों में बांटते समय विदेशगामी के लिए प्रशुल्क, विनिम्न दर रु. 44.55 अपनाते हुए जैसा कि मई 2006 में सम्मिश्र दर निर्धारित करते समय लागू किया गया था, अमरीकी डालर में निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार तटीय कन्टेनरों के लिए प्रशुल्क, संशोधित मार्गदर्शियों के अनुरूप, जिनका मई 2006 में दर निर्धारित करते समय भी प्रचलन किया गया था, विदेशगामी कन्टेनरों के लिए लागू दर के 60% पर निर्धारित किया गया है।

- (iv) सीएसएए ने जिस औद्योगिक श्रमिक विवाद का संदर्भ दिया है, वह इस प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप के लिए नहीं है। इसी प्रकार, कन्टेनरों को बांधने / खोलने संबंधी प्रचालन व्यवस्था में, जो आईजीटीपीएल 1 अगस्त 2006 से लागू करना चाहता था, परिवर्तन को अनुमोदन प्रदान करना या न करना इस प्राधिकरण ने आवश्यक नहीं समझा है। बीओटी करार के प्रासंगिक प्रावधान इस मुद्दे को संघालित करेंगे और सीओपीटी को उनका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

- (v) सीएसएए ने एक अन्य मुद्दा जो उठाया है वह, आईजीटीपीएल द्वारा प्रचालन का अधिग्रहण करने से पहले प्रभारित रु. 150/- प्रति बाक्स की तुलना में बांधने / खोलने संबंधी प्रभार की आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तावित रु. 225/- प्रति बाक्स की न्यायासंगतता के बारे में है।

सीएसएए द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन पर सीओपीटी ने निष्कर्ष निकाला है कि रु. 150/- प्रति बाक्स की दर निजी प्रचालकों द्वारा, यह प्रचालन आईजीटीपीएल द्वारा अधिग्रहीत करने से पहले प्रभारित की गई थी। तथापि, सीएसएए ने सीओपीटी को प्रासंगिक सेवा प्रदाताओं और लाइनों के बीच हुए अनुबंध की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की हैं जिनसे यह दर्शाया जा सके कि आईजीटीपीएल द्वारा उद्धृत दरें ठीक नहीं हैं।

सीओपीटी ने इस बात की पुष्टि की है कि आईजीटीपीएल द्वारा लगाई गई रु. 225/- प्रति बाक्स की दर निविदादाता प्रक्रियाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए बाजार आधारित दर है। आईजीटीपीएल द्वारा प्राप्त किया गया न्यूनतम प्रस्ताव रु. 230/- प्रति बाक्स बताया गया है। मई 2006 में दर के निर्धारण के दौरान भी आईजीटीपीएल ने कुछ ठेकेदारों के भाव प्रस्तावों की प्रतियां सीओपीटी को प्रस्तुत की थी और ये भाव प्रस्ताव रु. 236/- से रु. 250/- प्रति बाक्स के बीच थे।

सीओपीटी ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि बांधने / खोलने हेतु रु. 225/- प्रति बाक्स की दर जो आईजीटीपीएल ने लगाई है, बाजार आधारित दर है और न्यायसंगत है।

इस स्थिति की दृष्टि से, इस मोड़ पर इस दर की समीक्षा करने का कोई कारण नज़र नहीं आता है।

6. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण दिनांक 11 मई 2006 के आदेश में, निम्नानुसार पढ़े जाने हेतु संशोधन करता है:-

अनुसूचि 3.7 - पोत पर स्टीवेटरिंग प्रभार

विवरण	दर प्रति कन्टेनर	
	विदेशगामी (अमरी: डालर में)	तटीय (रुपये में)
बांधने खोलने / भंडारण संबंधी प्रभार	5.05	135/-
भंडार आयोजना और पर्यवेक्षण प्रभार	2.81	75/-

नोट्स:

- (1) ऊपर (i) पर बांधने / खोलने के निर्धारित प्रभार 1 जुलाई 2005 से लागू होंगे।
- (2) ऊपर (ii) पर भंडारण आयोजना और पर्यवेक्षण के लिए निर्धारित प्रभार 1 अक्टूबर 2005 से लागू होंगे।
- (3) ये प्रभार पोतों पर स्थलान्तरित किए गए कन्टेनरों पर भी लागू होंगे।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2006-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th August, 2006

No. TAMP/68/2005-IGTPL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the Order No. TAMP/68/2005-IGTPL dated 11th May, 2006 as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/68/2005 - IGTPPL

India Gateway Terminals Private Limited

Applicant

ORDER(Passed on this 23rd day of August 2006)

This Authority had passed an Order number TAMP/68/2005-IGTPPL on 11 May 2006 relating to proposal from the India Gateway Terminal Private Limited (IGTPPL) for levy of charges for lashing / unlashings, stowage planning and supervision charges. The Order was notified in the Gazette of India on 30 May 2006 vide Gazette No.91. This Authority in the said Order has approved the following consolidated charges with retrospective effect from 1 April 2005:

Schedule 3.7 - On board Stevedoring Charges

Particulars	Rate per Container	
	Foreign (in US\$)	Coastal (in Rs.)
Lashing unlashings / stowage planning and supervision charges	7.86	210/-

2.1: With reference to the said Order, the Cochin Steamer Agents Association (CSAA) has made a representation on various points. Subsequently, on 18 July 2006, an opportunity was given to the CSAA to express their views on the said Order passed by this Authority when the officials of the Cochin Port Trust, IGTPPL and some of the members of the Container Shipping Lines Association (India) were also present. The main points made by the CSAA in their written submission and at the hearing are summarised below:

- (i). The IGTPPL did not provide the relevant services from 1 April 2005; and, therefore, they should not raise any retrospective bills on the grounds that the rates were approved by TAMP with effect from 1 April 2005.
- (ii). If these charges are applied with retrospective effect from 1 April 2005, Shipping Lines would end up paying for the element of stowage / supervision twice, i.e. to IGTPPL as well as to Private Terminal Operators, in view of the on going Industrial Dispute.
- (iii). The IGTPPL have undertaken on board lashing / unlashings work only from July 2005 and Associated Yard Services from January 2006, and therefore, it would not be agreeable and fair for Shipping Lines to pay these charges in toto at the TAMP approved rate with retrospective effect from 1 April 2005.
- (iv). The consolidated charges fixed for this activity should be split up.
- (v). It has requested that the charges of Rs.125/- towards stowage planning and supervision included in the on board stevedoring should be kept in abeyance till the Industrial Dispute is settled.
- (vi). The documentary evidence of the rate quoted by some of the contractors, furnished by IGTPPL for Rs.250/- per box includes various other services, apart from lashing / unlashings work. No documentary evidence was called for by TAMP, and had this been asked for, the CSAA would have definitely provided the same, as the rate of Rs.150/- per box formed an integral part of the THC break-up.
- (vii). The rate quoted by IGTPPL which was relied upon by TAMP to fix the relevant charges did not correctly capture the market condition. The rates levied earlier for offering such services by the private contractors were much lower than the one off case produced by the IGTPPL.

26779708-2

2.2. The Terminal Operators Association of Kochi (TOAK) has also made a written submission reiterating most of the points made by the CSAA.

3.1. The submissions made by the CSAA and TOAK were forwarded to the IGTPPL for their comments. The IGTPPL in response has furnished its comments and has also clarified the points at the hearing held on 18 July 2006. The explanation furnished by IGTPPL in response to the submissions made by CSAA are as follows:

- (i). The Order of TAMP had been implemented prospectively and bills were raised only from the actual dates from which the relevant services were started to be provided by them. In order to avoid confusion, TAMP may amend the Order to specify the exact date from which the services were commenced.
- (ii). It has no reservation in bifurcating the consolidated charges as follows:
 - (a). Lashing / unlashng of containers - Rs.225/-
 - (b). Stowage planning - Rs.125/-
- (iii). They further announced that the terminal would not provide this service from 1 August 2006 and the agents could make their own arrangements for carrying out these operations. Nevertheless, it would levy the agents for the past period when it actually provided the services.
- (iv). CSAA should not shift the burden of industrial dispute between them and their workers by requiring the IGTPPL to absorb the cost of services provided

3.2. Taking into consideration the various issues raised in the hearing, the IGTPPL, CSAA and COPT were advised to initiate the following action:

- (i). The IGTPPL should inform the actual date from which the relevant services were provided by them. While conveying this information, they should also secure the agreement of CSAA on this date.
- (ii). The CSAA to produce copies of contract between the relevant service providers and the Lines to the COPT to show that the rate quoted by IGTPPL was not correct. Adequate documentary evidence should be provided in this regard to show that such rate was the prevailing rate in the market for a sufficiently longer duration of time prior to taking over the services by IGTPPL.
- (iii). The COPT should verify the authenticity of the claim made by CSAA and furnish its recommendation to TAMP.

4.1. With reference to the decisions taken at the hearing, the IGTPPL has furnished the relevant information / clarification along with consent letter of CSAA on the date issue as explained below.

- (i). The IGTPPL commenced rendering the lashing / unlashng services with effect from 1 July 2005.
- (ii). The services relating to stowage planning and supervision were rendered from October 2005, however, the charges for this service were levied from 1 July 2006 since the approval of the TAMP was awaited.
- (iii). The CSAA's letter forwarded by IGTPPL also confirms that the date of commencement of lashing / unlashng services by IGTPPL is with effect from 1 July 2005.

As regards stowage planning and supervision, the CSAA has stated that since the private terminat operators were required to provide this service till January 2006, this tariff item may be levied by IGTPPL from 1 January 2006 only.

4.2. The COPT has clarified the following:

- (i). It has confirmed the date of commencement of lashing / unlashng services by IGTPPL is from 1 July 2005, and stowage planning and supervision is from 1 October 2005.
- (ii). It has also furnished its report on the documentary evidence furnished by CSAA as summarised below:
 - (a). The Cochin Steamer Agents Association (CSAA) has forwarded certificates and bills collected from feeder vessel operators as documentary proofs, which shows that Rs.150/- per box was collected as lashing / unlashng charges from the MLO's, but they have not forwarded copies of contract between the relevant services providers and the lines to show that the rates quoted by IGTPPL are not correct.
 - (b). The bills furnished as documentary proofs relates to the period ranging from 2004 to March 2005. From this it can be concluded that Rs.150/- per box was prevailing in the market for sufficiently longer period of time prior to the IGTPPL taking over of the service from 1 July 2005.
 - (c). Prior to the IGTPPL taking over the terminal, Rs.150/- per box was charged towards lashing / unlashng. The present rate of Rs.225/- per box levied by the IGTPPL is based on offers received from tendering processes. The IGTPPL had invited fresh quotation for carrying out lashing / unlashng containers and the lowest offer received was Rs.230/- per box. The firms who have participated in present tender had in the past offered Rs.150/- per box but as per the present market rate lowest quotation is Rs.230/- per box. Therefore, the rate quoted by the IGTPPL at Rs.225/- per box for lashing / unlashng is reasonable.

5. With reference to the totality of the information furnished, the following position emerges:

- (i). The IGTPPL, COPT and CSAA all have unanimously confirmed that the date of commencement of lashing, unlashng services by IGTPPL is from 1 July 2005. Even the IGTPPL has suggested to specify the date from which the tariff is to be levied to avoid any ambiguity in this regard. That being so, the earlier Order is amended to specify that the tariff for lashing / unlashng will be applicable from 1 July 2005.
- (ii). As regards charges for stowage planning and supervision, the CSAA has made a vague remark that this tariff may be levied from 1 January 2006 on the grounds that the private operators were allowed to offer this service till that period. It has not specifically mentioned about the date of commencement of this service by the IGTPPL. The IGTPPL is entitled to levy tariff from the date from when it has started providing the services. The IGTPPL has reported that the services relating to stowage planning were rendered with effect from 1 October 2005. Even the COPT after verification at its end has confirmed that the stowage planning and supervision services were provided by the IGTPPL from 1 October 2005. That being so, the earlier Order is amended to specify that the tariff for stowage planning / supervision will be applicable from 1 October 2005.
- (iii). The CSAA has suggested to split the existing rate approved by this Authority. This is perhaps required since the application of the tariff for these two services are from different dates. The IGTPPL has expressed no reservation to bifurcate the existing rate into two i.e. lashing / unlashng charges and stowage planning and supervision charges.

The IGTPPL in its initial proposal itself had indicated the components of the composite on-board stevedoring rate which also finds a mention in the Order dated 11 May 2006. While bifurcating the composite rate, the tariff for foreign-going is prescribed in US dollar terms by adopting the exchange rate of Rs.44.55 as applied while prescribing the composite rate in May 2006. Likewise, the tariff for coastal container is prescribed at 60% of the rate applicable for the foreign container in line with the revised tariff guidelines which was also followed while prescribing the rate in May 2006.

- (iv). The Industrial Labour dispute referred by the CSAA is not for this Authority to intervene. Likewise, it is not found necessary for this Authority to approve or disapprove the proposed change in the operational arrangement in lashing / unlashings of containers which the IGTPL wanted to introduce from 1 August 2006. The relevant provisions of BOT Agreement would govern this issue and COPT should ensure its compliance.
- (v). Another main issue raised by the CSAA is about the reasonableness of the lashing / unlashings charges proposed at Rs.225/- per box by the IGTPL as against Rs.150/- per box levied prior to the IGTPL taking over the operations.

The COPT on verification of the documents furnished by the CSAA has concluded that Rs.150/- per box was levied by the private operators prior to the IGTPL taking over the operations. The CSAA has, however, not furnished copies of contract between the relevant services providers and the lines to the COPT to show that the rates quoted by IGTPL are not correct.

The COPT has confirmed that the rate of Rs.225/- per box levied by the IGTPL is a market based rate taking into consideration the offers received from tendering processes. The lowest offer received by IGTPL is reported to be Rs.230/- per box. During the fixation of the rate in May 2006 also, the IGTPL had furnished to COPT copies of quotation of some of the contractors which were in the range of Rs.236/- to Rs.250/- per box.

The COPT has categorically certified that the rate for lashing / unlashings at Rs.225/- per box levied by the IGTPL is a market based rate and is reasonable.

In view of this position, it is not found necessary to review this rate at this juncture.

6. In the result and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority amends the Order dated 11 May 2006 to read as follows:

Schedule 3.7. – On board Stevedoring

Particulars	Rate per Container	
	Foreign (in US\$)	Coastal (in Rs.)
(i) Lashing / Unlashings charges	5.05	135/-
(ii) Stowage planning and supervision charges	2.81	75/-

Notes:

- (1). The charges for lashing / unlashings prescribed at (i) above will be applicable from 1 July 2005.
- (2). The charges for Stowage planning and supervision prescribed at (ii) above will be applicable from 1 October 2005.
- (3). These charges would also apply on containers shifted onboard vessels.

A. L. BONGIRWAR, Chairman
[ADVT III/IV/143/2006-Exty.]